होगी तो वह भी आयेगी, सभी की आयेगी। मेरा अपना ख्याल था कि जब आपके नुमाइन्दे वहां पर बैठे थे तो फिर एतराज नही उठाना चाहिए था।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : हमारे पांडे जी ने मंजूर किया है इसलिए हमे कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष महोदय : फिर इनको यहां पर नही उठाना चाहिए था। लीडरों का फैसला होता है लेकिन ये यहा पर उठकर खड़े हो जाते है।

MR. SPEAKER I shall now put the motion moved by Shri Raj Bahadur, as modified, to the vote of the House.

The question is :

'That this House do agree with the Fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 17th November, 1971, subject to the modification that against item (27) of paragraph 2 of the Report, *for* "Monday, the 22nd November, 1971" "Tuesday, the 23rd November, 1971" be *substituted*.

The motion was adopted.

12.53 hrs.

FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY) : Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952."

The motion was adopted.

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY : Sir, I introduce the Bill.

12.54 hrs.

STATEMENT RE. FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY) : Sir, I lay on the Table a copy of the explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Forward Contracts (Regulation) Amendment Ordinance, 1971, as required under rule 71 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Sir, I move for leave to introduce a Bill to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952."

The motion was adopted.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I introduce the Bill.

---

12 55 hrs.

MOTION RE. ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES—*Contd.*

MR. SPEAKER : Shri Mohapatra to continue his speech. He is absent. Shri Sambhali.

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : सदर साहब यह लिसानी अक्लियतों के कमिश्नर साहब की 144 सफे की रिपोर्ट हमारे सामने है। कमिश्नर साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं और हम समझते है कि उन्होंने मेहनत की है, बड़ी

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Sectio 2, dated 18-11-71.

[श्री इसहाक सम्भली]

दौड़-धूप की है लेकिन रिपोर्ट पढ़ने के बाद बड़ी मायूसी होती है। इसमें जा बजा यह लिखा गया है कि ये फैसले किये गये, वे फैसले किये गये, ये आर्डर जारी दिये गए लेकिन देखने की बात यह है कि उन फैसलों और उन आर्डर्स पर अमल-दरामद भी हुआ या नहीं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर अमल-दरामद के लिए हम देखें तो लिंग्वीस्टिक माइनारिटीज के बारे में सूबों की सरकारों ने और खुद हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जितनी मुजरियाना खामोशी और जितनी लापरवाही बरती हैं वह शायद किसी दूसरे मसले में देखने को नहीं मिलेगी। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी उर्दू स्पीकिंग लिंग्वीस्टिक माइनारिटी की जिस तरह से हकतलफी की गई है वह तो मैं अर्ज करूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी माइनारिटीज की तकलीफे दूर करने में कोई ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं होता था उनको भी नजरन्दाज किया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि जहां पर दस बच्चे होंगे उनके वास्ते उनकी मादरी भाषा में तालीम का इन्तजाम किया जायेगा, जहां चालीस बच्चे होंगे एक जबान के जानने वाले उनके लिए क्लास खोला जायेगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब ने यह भी जानने की तकलीफ गवारा की या नहीं कि इसपर अमल दरामद है या नहीं ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अबतक जहां कहीं कुछ अमल दरामद था, बाज जगह उनको भी खत्म किया जा रहा है। बिहार के स्कूलों कालेजों में मगध यूनिवर्सिटी में आप देखें कि अबतक वहां यह था कि जो स्टूडेन्ट बगाली में जवाब लिखना चाहते थे, उड़िया में जवाब लिखना चाहते थे, उर्दू में जवाब लिखना चहते थे उनको उसकी इजाजत होती थी। ... (व्यवधान) लेकिब निहायत अफसोस की बात है मगध यूनिवर्सिटी में किसने निर्णय किया—मेरे भाई ने फर्माया कि निर्णय किया—किसने निर्णय किया यूनिवर्सिटी एथारिटीज ने निर्णय किया, गार्जियन्स ने निर्णय नहीं किया। मगध यूनिवर्सिटी में इन तीनों जवानों में जवाब देने का सिलसिला खत्म किया गया। यहां बंगला स्पीकिंग माइनारिटीज वे इस बारे में सवाल उठाया, उड़िसा स्पीकिंग माइनारिटीज ने सवाल उठाया, श्री चिंतामणि पाणिग्रही ने सवाल उठाया, श्री रामावतार शास्त्री ने इस बारे में सवाल उठाया तो कुछ दिन के लिये रुका लेकिन यह प्रथा जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से और जबानों में जवाब देने का सिलसिला खत्म किया जा रहा है, मुझे मालूम हुआ है कि पटना यूनिवर्सिटी में भी यह कोशिश की जा रही है, और कालेजों में भी यह कोशिश की जा रही है। बिहार की तमाम यूनिवर्सिटीज में यह कोशिश जा रही है तो जब अमल दरामद की तरफ कोई तवज्जह नहीं तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतनी मेहनत और इतना पैसे का खर्चा सब बेकार होकर रह जाता है। पंजाबी जबान को सरकारी दर्जा दिया गया, मैं शुक्रगुजार हूं, सही दिया गया बल्कि बहुत पहले यह दर्जा मिलना चाहिए था।

लेकिन मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इसका वहां पर अमलदरासद क्या है? क्या यह सही नहीं है कि वहां पर दफतरों में हिन्दी भी नहीं बल्कि...

अध्यक्ष महोदय : आप दो बजे कन्टीन्यू कीजियेगा।

13.01 hrs

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

MOTION RE. ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES—*Contd.*

श्री इसहाक सम्भली : उपाध्यक्ष महोदय,

पंजाब में पंजाबी सरकारी जबान हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा सरकारी जबान होने के बावजूद अमलदरामद क्या हुआ ? पजाबी जबान मे वहा काम नही हो रहा है । हमारे बुजुर्ग और हमारे मुल्क के रहनुमा सरदार दरबारा सिंह शायद इस बारे मे कुछ फरमायेंगे, लेकिन इतना ही कहूँगा कि इस वक्त वहाँ न पजाबी जबान मे काम हो रहा है और न हिन्दी जबान मे काम हो रहा है, सिर्फ अंग्रेजी जबान मे रहा है । आखिर इस चीज को देखना किसका काम है ? क्या इन कमिश्नर साहब का काम यह नही है ?

मै आप से अर्ज करना चाहता हू कि पजाबी शब्द कोश, यानी डिक्शनरी बनाने का जिक्र हुआ । जाहिर है कि डिक्शनरी बनना बहुत जरूरी है, लेकिन मुल्क को आजाद हुए 24 साल होने के बाद भी पजाबी की डिक्शनरी तैयार नही हुई ।

इसी तरह से आप उर्दू के बारे मे देखिए । सब से बडी लिंग्विस्टिक माइनारिटी, उर्दू स्पीकिंग पीपल्स के साथ क्या हो रहा है । इस मौके पर मै जरूरी समझता हू कि आन्ध्र प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करू क्योकि उन्होने अपने यहा उर्दू को बहुत अहमियत दी । हमारा फर्ज है कि उन का शुक्रिया अदा करे । लेकिन इसके साथ-साथ यू० पी० और बिहार मे, जो उर्दू के खास सेंटर है, उर्दू के साथ क्या हो रहा है ? क्या कसूर है उर्दू का ? मै अपने तजुर्बे की बिना पर कह सकता हू कि जब भी कोई अफसर जाता है तो कह दिया जाता है कि उर्दू पढने वाले बच्चे नही है, उन की दस की तादाद नही है, चालीस की तादाद नही है, लेकिन मै उन स्कूलो के नाम बतला सकता हूँ जहा 90 परसेन्ट नही, 95 परसेन्ट उर्दू पढ़ने वाले बच्चे मौजूद है, मगर कह दिया जाता है कि उर्दू की तालीम का इन्तजाम नही हो सकता । यू० पी० के बारे मे यह कहा जाता है कि जहा दस लड़के होगे वहा उर्दू तालीम का इन्तजाम किया जायेगा । हमारे मुख्य मन्त्री त्रिपाठी जी कहते है कि ऐडवान्स मे नाम रजिस्टर कराये जायेगे और जिन लोगो ने लिख कर दे दिया है उन को हम उर्दू तालीम दिलवायेगे, लेकिन उन का कुछ इन्तजाम नही किया गया । इस नाइन्साफी का नतीजा यह हुआ है कि हम उर्दू की दौलत से तेजी मे महरूम होते चले जा रहे है । उर्दू वह जबान है जो लिखने मे बहुत थोडी जगह लेती है, उर्दू वह जबान है जिस ने दर्जियों जबानो को अपने मे समा लिया है । उर्दू स्पीकर जितना तेज बोल सकते और जितनी जल्दी इस को लिख सकते हैं उसको कहने की जरूरत नही है । उर्दू जबान वह है कि उस की स्क्रिप्ट जानने की वजह से बगैर किसी कोशिश के हम दुनिया के तेरह मुल्कों की स्क्रिप्ट जान जाते है ।

लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बावजूद भी उनको उन के हकूक से महरूम किया जा रहा है । यह वादा किया गया था, यह पुरानी माग थी कि उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की जाए, उर्दू कालेज कायम किये जाये । मुझे खुशी है और मै मुबारिकवाद देता हू तमिलनाडु को, मैसूर को, केरल को कि वहा पर उर्दू कालेज मौजूद है । लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू कालेजों से महरूम है । आजादी से पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी उर्दू मीडियम की एक यूनिवर्सिटी थी । लेकिन आजादी के बाद उसको खत्म कर दिया गया है । अब वह उर्दू मीडियम की यूनिवर्सिटी नही रही है । करोडो उर्दू जानने वाले हिन्दुओ और मुसलमानों की यह माग है कि उर्दू यूनिवर्सिटी मुल्क मे होनी चाहिए लेकिन वह नही बनाई गई है । क्या कसूर किया है उर्दू की हिमायत करने वालो मे या उर्दू बोलने वालो ?

स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं और वहा क्या हो रहा है उसकी तरफ कमिशनर साहिबा ने तवज्जह दिलाई है । लेकिन खुद सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे क्या हो रहा

[श्री इसहाक सम्भली]

है और वह खुद क्या कर रही है, इसको आप देखें। दिल्ली के लिए सैकिड जबान उर्दू हो, इसकी मांग की जाती है। मै जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्या दुशवारी पेश आ रही है कि वह इसको दूसरी जबान डिक्लेयर नही करती है ? हम पहली जबान की माग नही करते हैं। हिन्दी हमारी जबान है। हमको हिन्दी पर फख्र है। हम को खुशी है कि हमारी जबान हिन्दी है, हमारी सरकारी जबान हिन्दी है। लेकिन उर्दू हमारी मदर टग है, हमारी मादरी जबान है। इसलिए यह जरूरी है कि उसको अपना अधिकार उसको अपने हकूक मिले। यह कह देने के लिए कि एक लाख रुपया बतौर एवार्ड के दे दिया गया है कुछ राइटर्ज को या एक लाख रुपया अजुमने तरक्की उर्दू को दे दिया गया है, उर्दू की तरक्की नही होगी, उसका भला नही होगा, उसको जिन्दगी नही मिलेगी। उसको अगर जिन्दगी देना है और जिन्दा रखना है तो आपको उसे दूसरी सरकारी जबान डिक्लेयर करना होगा। तभी उसके साथ आप इसाफ करेंगे।

उर्दू के साथ इसाफ न करने का नतीजा क्या हो रहा है ? सबसे बडी लिंग्विस्टिक माइनोरिटी उर्दू के साथ जो नाइसाफी की जा रही है उसका नतीजा यह हो रहा है कि जो दूसरी लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज है, उस के साथ भी नाइसाफी करने की आदत बनती जा रही है और बन गई है। जो छोटी-छोटी दूसरी जबाने बोलने वाले लोग हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी जबान को नहीं बल्कि अंग्रेजी जबान को अपनी आफिशल जबान करार दे दिया है और दे रहे है। नागालैंड को आप देखें। उसने अंग्रेजी को सरकारी जबान डिक्लेयर किया है। मेघालय की सरकार ने अंग्रेजी को सरकारी जबान डिक्लेयर किया है। मुझे यकीन है कि अंग्रेजी से उनको मुहब्बत नहीं है। यह विदेशी जबान है। लेकिन आप देखें कि फिर भी जो उनकी जबान है, जिस जबान को वे बोलते है, उसकी तरक्की के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है, उसको सक्रिप्ट नही दी गई है, उसके लिए लिट्रेचर फराहम नही किया गया है, उसको उसका दर्जा नही दिया गया है। यह हमारे मुंह पर एक बहुत बडी चपत है कि हम वहा की लोकल जबान को आफिशल जबान न बनाकर अंग्रेजी को मजबूरन वह दर्जा दे देते हैं। मैं समझता हू कि उडिया, बगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड आदि मे अगर इतना रिच लिट्रेचर न होता जो है वे इतनी रिच लेंगुएजिज न होती जितनी वे आज है तो इस बात का पूरा-पूरा अदेशा था कि वे भी अपने आप को आफिशल लेंगुएजिज न बना पाती। क्या ये जो सब चीजे है इन पर हम कभी तवज्जह देंगे, इनको कभी हम देखेंगे।

इस वास्ते बडा भारी जो सवाल है वह लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज का सवाल है। उनके सवाल को हल किये बिना यह जो कमिशन की रिपोर्ट है यह बेमानी हो जाती है। ये जो चीजे है इन पर किस तरह से अमल दरामद हो रहा है, उसकी रिपोर्ट पर किस तरह से अमल किया जा रहा है, सूबो या सेन्टर की तरफ से किस तरह से उसकी सिफारिशों को इगनोर किया जा रहा है, इन सब चीजो के बारे मे अगर वह कमिशन रिपोर्ट नही देता है तो उसका कोई फायदा नही है। मुझे खुशी है कि कमिश्नर साहिबा ने काफी मेहनत की है। लेकिन यह देख कर मुझे दुख हुआ है कि इन चीज से उनकी रिपोर्ट खाली है। नई कमिश्नर साहिबा गई और जा कर उन्होने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात की, उन से वह मिली। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सम्झ बाते करने वाले आदमी है। उन्होने लम्बी-लम्बी बाते कही। यह कहा कि हमने यह आर्डर कर दिया है, वह आर्डर कर

दिया है उर्दू के लिए और इस सब को सुन कर वह वापिस आ गई। इस तरह से इनक्वायरी नहीं हुआ करती है, इस तरह से उर्दू के साथ इंसाफ नहीं होगा, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। उनको चाहिये था कि वह उर्दू स्कूलों में जातीं वगैर इत्तिला दिये जातीं। उनको चाहिये था कि उन जगहों पर जाती जहां से उर्दू के बारे में शिकायतें आई हैं। उनको चाहिये था कि जा कर देखती कि जो सरकारी आर्डर्ज हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं।

बड़ा भारी सवाल यह है कि उर्दू के साथ इन्साफ नहीं हो रहा है, नाइन्साफी हुई है। लेकिन इतना ही नही कि उर्दू के साथ इंसाफ नही हो रहा है बल्कि इसके और भी बुरे नतीजे निकले है। इसके नतीजे के तौर पर जो तमाम लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज है उनके साथ भी नाइंसाफी करने की आदत बन गई है और उस कारण वे लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज मुतमईन नहीं हैं, वे डिससैटिसफाइड हैं। जा कर आप संथाल परगना में देख लें। वहां के लोगों से बात करके देख लें। वहां लोगों की अपनी भाषा नही है क्या ? जितने भी कबायली है उनकी अपनी जबान है। बड़ी मीठी जबान है। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है कि माइनोरिटी लेंगुएजिज को सप्रैस करो, उनको दबाओ। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो बड़ी जबानें हैं वे भी दबाई जा रही हैं। छोटी छोटी जबनों को भी दबाया जा रहा है, वे भी दब रही है। यह बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी अंग्रेजी के खिलाफ नही है, अंग्रेजी की विरोधी नहीं है, हिन्दी की विरोधी नहीं है, लेकिन वह यह जरूर चाहती है कि हमारे यहां की जो अपनी जबानें हैं वे आगे बढ़ें। मैंने हिन्दुस्तान से बाहर देखा है। रूस में भी मेरा जाना हुआ है। मुझे देख कर ताज्जुब हुआ कि वहां छोटी छोटी कंम्युनिटीज, छोटे छोटे कबालियों की अपनी जबानें हैं और उनका अपना लिट्रेचर है, और उन जबानों को सक्रिप्ट दी गई है। हमारे यहां क्या होता है ? इतना बड़ा हमारा मुल्क है, इतना शानदार हमारी रवायात हैं लेकिन जिन जबानों को हम बोलते हैं चूंकि उनको उनका उचित स्थान नहीं दिया गया है, इस वास्ते बेचैनी पैदा हो गई है। पहाड़ों पर बेचैनी है। गढवाली जो बोलते है, उन में बेचैनी है। कुमायूं के रहने वालें लोगों में बेचैनी है। वह बेचैनी सिर्फ इस वास्ते हैं कि उनकी जो जबानें हैं उनको दबाया जा रहा है। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है अगर यह कहा जाएगा कि यह मुसलमानों की जबान है तो यह इतनी बेइसाफी होगी कि शायद इतना बड़ा झूठ इस आसमान के नीचे बोला न गया हो। मैं पूछना चाहता हूं कि उर्दू का सबसे बड़ा राइटर आज हिन्दुस्तान में कौन है ? क्या कृष्ण चन्द्र नही है ? उर्दू का हिन्दुस्तान में सब से बड़ा शायर कौन है ? क्या रघुपति सहाय फिराक गोरख पुरी नहीं है ? इसको मुसलमानों की ही जबान कहना इसके साथ नाइंसाफी करना होगा। कभी कह दिया जाता है कि यह तो पाकिस्तान की सरकारी जबान है। पाकिस्तान वालों की आफिशल लेंगुएज तो बंगला भी है। चूंकि उसको दबाने की कोशिश की गई, उसके साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की गई क्या इसी वास्ते यहां गुस्सा और रोष पैदा नही हुआ जिसकी वजह से बंगला देश बना ? पाकिस्तान के फौजी टोले को, वहां के डिक्टेटरों को जबान के मसले ने फना कर दिया।

एक और बड़ा सवाल है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले थोड़ी थोड़ी तादाद में मौजूद है। कलकत्ता में नेपाली बोलने वाले हैं। बनारस में बंगला बोलने वाले मौजूद है। अहमदाबाद में मलयालम बोलने वाले मौजूद हैं। वे भी इण्डियन सिटिजन हैं। इंडियन सिटिजन होने के नाते जैसे हमारा फर्ज है कि हम उनकी फिजिकल सिक्योरिटी

[श्री इसहाक सम्भली]

का इंतजाम करें, उसी तरह से हमारा फर्ज हो जाता है कि उनकी लेंगुएज का सिक्योरिटी का भी इतजाम करें। वहां पर उनको उनकी अपनी जबान में तालीम दें। मैंने बहुत तलाश किया इस रिपोर्ट में कि कही इसके बारे में कोई मुझे सिफारिश मिले लेकिन नही मिली। इसके बारे में यह रिपोर्ट खामोश है। जबान सिर्फ खयालात का इजहार करने के लिए नहीं होती है, जबान एक कल्चर होती है, तमद्दुन बताती है, रहन सहन की रवायात बताती है। इसको अगर मिटाने की कोशिश की गई, जो की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के साथ यह इसाफ नही होगा। यह बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इस नाइंसाफी को खत्म करना जरूरी है।

मैं समझता हूं कि वन मैन लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज कमिशन से काम नही चलेगा। इसको खत्म करके पार्लिमेंट की डैमोक्रैटिव सैक्युलर पार्टियो के कम से कम तीन नुमाइन्दे ले कर इस कमिशन को बनाया जाए। जिस तरह से एग्रिकलचरल प्राइमिस कमिशन है या और कमिशन हैं उसी तरह का यह कमिशन बनाया जाये। इसमें रिटायर्ड एम० पी० न हों लेकिन जो एम० पी० चुन कर आएं उनको लिया जाए। वे स्टेट्स में जाएं और जा कर वहां हो रही नाइंसाफियों को देखें और यहां पालियामेट में उनको बयान करें, उसके नोटिस में इनको लाएं। अब भी वक्त है सरकार इन नाइंसाफियो को दूर करे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैरिटरीज है, उसके जो इलाके है वहां पर लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को उनके पूरे राइट दिये जाएं और इसके सबूत के तौर पर सब से पहले दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान डिक्लेयर किया जाए। उर्दू जबान यहां पढ़ाई जा रही है लेकिन किताबे गायब हैं। दिल्ली में टैक्स्ट बुक नैशनलाज्ड हैं। कोई और उनको छाप नहीं सकता है। लेकिन इतनी थोड़ी तादाद में यहा उनको छापा गया है कि उर्दू पढ़ने वाले मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको किताबें मयस्सर नहीं होती हैं।

यह स्टेट गवर्नमेंट्स की बात नहीं है, बल्कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में जो नाइंसाफियां अभी तक हुई है, उनको जारी नही रहने दिया जायेगा। हमें खुशी है कि यह डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में अलग थलग और बेकार कर के रख दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन नाइन्साफियो को दूर करने के लिए कदम उठायेगी।

شری اسحاق سنبھلی (امروہا) یہ لسانی اقلیتوں کے کمشنر صاحب کی ۱۴۴ صفحوں کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ کمشنر صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ بڑی دوڑ دھوپ کی ہے لیکن رپورٹ پڑھنے کے بعد بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اس میں جابجا یہ لکھا گیا ہے یہ فیصلے کئے گئے یہ آرڈر جاری کئے گئے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان فیصلوں اور آرڈرز پر عمل درآمد بھی ہوا یا نہیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر عمل درآمد کے لئے ہم دیکھیں تو لنگوسٹک مائنارٹیز کے بارے میں صوبوں کی سرکاروں نے اور خود ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے جتنی مجرمانہ خاموشی اور جتنی لاپرواہی برتی ہے وہ شاید کسی دوسرے مسئلے میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اردو سپیکنگ لنگوسٹک مائنورٹیز کی جس طرح سے حق تلفی کی گئی ہے وہ میں عرض کروں گا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز کی تکلیفیں دور کرنے میں کوئی زیادہ دشواری کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس میں لکھا گیا کہ جہاں پر دس بچے ہوں گے

ان کے واسطے ان کی مادری بھاشا میں تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ جہاں چالیس بچے ہوں گے ایک زبان کے کلاس کھولی جائے گی۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کمشنر صاحب نے یہ بھی جاننے کی تکلیف گوارا کی یا نہیں کہ اس پر عمل درآمد ہے یا نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جہاں کہیں کچھ عمل درآمد تھا بعض جگہ اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ بہار کے سکولوں و کالجوں میں مگدھ یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ اب تک وہاں یہ تھا کہ جو سٹوڈنٹ بنگالی میں جواب لکھنا چاہتے تھے ہندی میں جواب لکھنا چاہتے تھے۔ اردو میں جواب لکھنا چاہتے تھے ان کو اس کی اجازت ہوتی تھی لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ مگدھ یونیورسٹی میں کس نے ترمیم کیا۔ میرے بھائی نے فرمایا کہ ترمیم کیا۔ کس نے ترمیم کیا یونیورسٹی اتھورٹی نے ترمیم کیا گارڈینز نے ترمیم نہیں کیا۔ مگدھ یونیورسٹی میں ان تینوں زبانوں میں جواب دینے کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ وہاں بنگلہ سپیکنگ مائنورٹیز نے اس بارے میں سوال اٹھایا۔ اردو سپیکنگ مائنورٹیز نے سوال اٹھایا۔ شریمتی منی

ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اُردو وہ زبان ہے جو لکھنے میں بہت تھوڑی جگہ لیتی ہے۔ اُردو وہ زبان ہے جس نے دسیوں زبانوں کو اپنے میں سمو لیا ہے۔ اُردو سپیکر جتنا تیز بول سکتے ہیں اور جتنی جلدی اسکو لکھ سکتے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اُردو زبان وہ ہے کہ اس کی سکرپٹ جاننے کی وجہ سے بغیر کسی کوشش کے ہم دُنیا کے ۱۳ ملکوں کی سکرپٹ جان جاتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ رہا سہا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پُرانی مانگ تھی کہ اُردو یونیورسٹی قائم کی جائے۔ اُردو کالج قائم کئے جائیں۔ مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں تامل ناڈو کو۔ میسور کو۔ کیرل کو کہ وہاں پر اُردو کالج موجود ہیں۔ لیکن اتر پردیش اور بہار اُردو کالجوں سے محروم ہیں۔ آزادی سے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی اردو میڈیم کی ایک یونیورسٹی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اُردو میڈیم کی یونیورسٹی نہیں رہی ہے۔ کروڑوں

اُردو جاننے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کی یہ مانگ ہے کہ اُردو یونیورسٹی ملک میں قائم کی جائے لیکن وہ نہیں مانی گئی ہے۔ کیا قصور کیا ہے اُردو کی حمایت کرنے والوں نے اور اُردو بولنے والوں نے۔

سٹیٹ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی طرف کمشنر صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور وہ خود کیا کر رہی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں۔ دہلی کے سیکنڈ زبان اُردو ہو۔ اس کی مانگ کی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کو کیا دشواری آ رہی ہے کہ وہ اس کو دُوسری زبان ڈیکلیئر نہیں کرتی ہے۔ ہم پہلی زبان کی مانگ نہیں کرتے ہیں۔ ہندی ہماری زبان ہے۔ ہم کو ہندی پر فخر ہے۔ ہم کو خوشی ہے کہ ہماری زبان ہندی ہے۔ ہماری پرمپرا سرکاری زبان ہندی ہے۔ لیکن اُردو ہماری مدر ٹنگ ہے۔ ہماری مادری زبان ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنا ادھیکار اس کو

اپنے حقوق ملیں۔ یہ کہہ دینے سے کہ ایک لاکھ روپیہ بطور ایوارڈ کے دے دیا گیا ہے۔ کچھ رائٹرز کو یا ایک لاکھ روپیہ انجمن ترقی اُردو کو دے دیا گیا ہے۔ اُردو کی ترقی نہیں ہو گی۔ اس کا بھلا نہیں ہوگا۔ اس کو زندگی نہیں ملے گی۔ اس کو اگر زندگی دینا ہے اور زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اسے دُوسری سرکاری زبان ڈیکلیئر کرنا ہوگا۔ تبھی اس کے ساتھ آپ انصاف کریں گے۔

اُردو کے ساتھ انصاف نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی لنگوسٹک مائنورٹی اُردو کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دُوسری لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ اور بن گئی ہے جو چھوٹی چھوٹی دوسری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں مجھے دُکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو نہیں بلکہ انگریزی زبان کو اپنی آفیشل زبان قرار دے دیا ہے اور دے رہے ہیں۔

پانیگراہی نے سوال اٹھایا۔ شری رام اوتار شاستری نے اس بارے میں سوال اُٹھایا تو کچھ دن کے لئے رکا۔ لیکن یہ پر تھا جس طرح سے چل رہی ہے جس طرح سے اور زبانوں میں جواب دینے کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کولجوں میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بہار کی تمام یونیورسٹیز میں یہ کوشش کی جا رہی ہے تو اب عمل درآمد کی طرف کوئی توجہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی رپورٹ اتنی محنت اور اتنا پیسے کا خرچا سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ پنجابی زبان کو سرکاری درجہ دیا گیا۔ میں شکرگزار ہوں۔ صحیح دیا گیا بلکہ بہت پہلے یہ درجہ ملنا چاہیئے تھا۔ لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا وہاں پر عمل درآمد کیا ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ وہاں پر دفتروں میں ہندی بھی نہیں بلکہ . . . . . .

اُپا دھکش مہودے۔ پنجاب میں پنجابی سرکاری زبان ہوئی۔ لیکن جیسا میں نے کہا سرکاری زبان ہونے کے باوجود عمل درآمد

کیا ہوا۔ پنجابی زبان میں وہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے ملک کے رہنما سردار دربارہ سنگھ شاید اس بارے میں کچھ فرمائیں گے۔ لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت وہاں نہ پنجابی زبان میں کام ہو رہا ہے اور نہ ہندی زبان میں کام ہو رہا ہے۔ صرف انگریزی زبان میں کام ہو رہا ہے۔ آخر اس چیز کو دیکھنا کس کا کام ہے۔ کیا ان کمشنر صاحب کا نہیں ہے۔

میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجابی شبد کو۔ یعنی ڈکشنری بنانے کا ذکر ہوا۔ ظاہر ہے کہ ڈکشنری بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ملک کو آزاد ہوئے ۲۴ سال ہونے کے باوجود بھی پنجاب کی ڈکشنری تیار نہیں ہوئی۔

اس طرح سے آپ اُردو کے بارے میں دیکھئے۔ سب سے بڑی لنگوسٹک مائنورٹیز۔ اُردو سپیکنگ پیوپلز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس موقعہ پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آندھرا پردیش سرکار کا شکریہ ادا کروں کیونکہ انہوں نے اپنے یہاں

اُردو کو بہت اہمیت دی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو۔پی اور بہار میں جو کہ اُردو کے خاص سینٹر ہیں۔ اُردو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا قصور ہے اُردو کا۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی افسر جاتا ہے جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اُردو پڑھنے والے بچے نہیں ہیں۔ ان کی دس کی تعداد نہیں ہے۔ چالیس کی تعداد نہیں ہے۔ لیکن میں ان سکولوں کے نام بتا سکتا ہوں جہاں نوّے پرسینٹ نہیں چالوے پرسینٹ اردو پڑھنے والے بچے موجود ہیں۔ مگر کہہ دیا جاتا ہے کہ اُردو کی تعلیم کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یوپی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں دس بچے ہونگے۔ وہاں اُردو کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ ہمارے مکھیہ منتری ترپاٹھی جی کہتے ہیں کہ ایڈوانس سے نام رجسٹر کروائے جائینگے اور جن لوگوں نے لکھ کر دے دیا ہے ان کو ہم اُردو تعلیم دلوائیں گے۔ لیکن ان کچھ انتظام نہیں کیا گیا اس ناانصافی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم اُردو کی دولت سے تیزی سے محروم

ناگالینڈ کو آپ دیکھیں انہوں نے انگریزی کو سرکاری زبان ڈیکلیئر کیا ہے۔ میگھالیہ کی سرکار نے انگریزی کو سرکاری زبان ڈیکلیئر کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انگریزی سے ان کو محبت نہیں ہے۔ یہ بدیشی زبان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی جو ان کی اپنی زبان ہے۔ جس زبان کو وہ بولتے ہیں۔ اس کی ترقی کے لئے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اس کو سکرپٹ نہیں دی گئی ہے۔ اس کے لئے لٹریچر فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ اس کو اس کا درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ ہمارے منہ پر ایک بہت بڑی چپت ہے کہ ہم وہاں کی لوکل زبان کو آفیشل زبان نہ بنا کر/انگریزی کو مجبوراً وہ درجہ دے دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اڑیہ۔ بنگلہ۔ تامل۔ تیلگو۔ ملیالم۔ کنڑا ری میں اگر اتنا رچ لٹریچر نہ ہوتا جو ہے وہ اتنی رچ لنگویج نہ ہوتی۔ جتنی وہ آج ہیں۔ تو اس بات کا پورا پورا اندیشہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو آفیشل لنگویج نہ بنا پاتی۔ کیا یہ جو سب چیزیں ہیں ان پر کبھی ہم توجہ دیں گے۔ ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔

اس واسطے بڑا بھاری سوال ہے لنگوسٹک مائنورٹیز کا سوال ہے۔ اس کے سوال کو حل کئے بنا یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان پر کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کی رپورٹ پر کس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے۔ صوبوں یا سینٹر کی طرف سے کس طرح سے اس کی سفارشوں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اگر وہ کمیشن رپورٹ نہیں دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کمشنر صاحب نے کافی محنت کی ہے لیکن یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے کہ اس چیز سے ان کی رپورٹ خالی ہے کہ کمشنر صاحب گئیں اور جا کر انہوں نے [illegible] کے چیف منسٹر سے بات کی ان سے وہ ملیں۔ چیف کمشنر صاحب بہت عمدہ باتیں کرنے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے لمبی لمبی باتیں کہیں۔ یہ کہا کہ ہم نے یہ آرڈر کر دیا ہے وہ آرڈر کر دیا ہے۔ اردو کے لئے اور اس سب کو سن کر

وہ واپس آگئیں۔ اس طرح سے انکوائری نہیں ہوا کرتی ہے اس طرح سے اُردو کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس کو انصاف نہیں مل سکتا۔ ان کو چاہیئے تھا کہ وہ اُردو سکولوں میں جاتیں بغیر اطلاع دیئے جاتیں۔ ان کو چاہیئے تھا کہ ان جگہوں پر جاتیں جہاں سے اُردو کے بارے میں شکایتیں آئی ہیں۔ اور ان کو چاہیئے تھا کہ جا کر دیکھیں کہ جو سرکاری آرڈرز ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں

بڑا بھاری سوال یہ ہے کہ اُردو کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ ناانصافی ہوئی ہے لیکن اتنا ہی نہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ اس کے اور بھی بُرے نتیجے نکلے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر جو تمام لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی عادت بن گئی ہے۔ اس کارن اور اس کارن وہ لنگوسٹک مائنورٹیز منتیں نہیں [illegible] ڈسپلنا یئڈ ہیں جا کر آپ سنتھال پرگنا میں دیکھ لیں۔ وہاں لوگوں کی اپنی

ہے۔ [illegible] زبان ہیں لیکن ہماری عادت بن چکی ہے کہ مائنورٹیز لنگویج کو سپریس کرو۔ ان کو دباؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو [illegible] زبانیں ہیں وہ بھی دبائی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی زبانوں کو بھی دبایا جا رہا ہے وہ بھی دب رہی ہیں یہ بات مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے حدف نہیں ہے انگریزی کی و [illegible] نہیں ہے ہندی کی ورودھی ہیں لیکن یہ وہ ضرور چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں کی جو اپنی زبانیں ہیں وہ آگے بڑھیں میں نے ہندوستان سے باہر دیکھا ہے۔ روس میں بھی میرا جانا ہوا ہے مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی اپنی زبانیں ہیں اور ان کا اپنا لٹریچر ہے۔ اور ان زبانوں کو سکرپٹ دی گئی ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ بھارت ہمارا ملک ہے۔ اتنی شاندار ہماری روایات ہیں لیکن جن زبانوں کو ہم بولتے ہیں [illegible] ان کا اچت استھان نہیں دیا گیا ہے اس واسطے

[illegible] پیدا ہو گئی ہے [illegible] زبان بولنے میں [illegible] والے لوگوں میں [illegible] زبانیں ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے جہاں تک اُردو کا تعلق ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو یہ اتنی بے انصافی ہوگی کہ شاید اتنا بڑا جھوٹ اس آسمان کے نیچے بولا گیا ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اُردو کا سب سے بڑا [illegible] آج ہندوستان میں کون ہے۔ کیا کرشن چندر نہیں ہے۔ اُردو کا ہندوستان میں سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ کیا رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نہیں ہے۔ اس کو مسلمانوں کی ہی زبان کہنا اس کے ساتھ ناانصافی کرنا ہوگا۔ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کی سرکاری زبان ہے۔ پاکستان والوں کی آفیشل لنگویج تو بنگلہ بھی ہے۔ چونکہ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کی گئی کب اسی واسطے وہاں غصہ اور روش پیدا نہیں ہوا۔ جس کی وجہ سے

آج بنگلہ دیش بنا پاکستان کے فوجی ٹولے کو وہاں کے ڈکٹیٹروں کو زبان کے مسئلے نے فنا کر دیا۔

ایک اور بڑا سوال ہے۔ مختلف شہروں میں مختلف زبانیں بولنے والے تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں کلکتہ میں نیپالی بولنے والے ہیں۔ بنارس میں بنگلہ بولنے والے موجود ہیں۔ احمد آباد میں ملیالم بولنے والے موجود ہیں۔ وے بھی انڈین سیٹیزن ہیں۔ انڈین سیٹزن کے ناطے جیسے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی فزیکل سیکیورٹیز کا انتظام کریں۔ اسی طرح سے ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی لنگویج کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کریں۔ وہاں پر ان کو ان کی اپنی زبان میں تعلیم دیں۔ میں نے تلاش بہت کیا اس رپورٹ میں کہ کہیں اس کے بارے میں کوئی مجھے سفارش ملے۔ لیکن نہیں ملی۔ اس کے بارے میں یہ رپورٹ خاموش ہے۔ زبان صرف خیالات کا اظہار کرنے کے لئے نہیں ہوتی ہے۔ زبان ایک کلچر ہوتی

اگر مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جو کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوگا یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس ناانصافی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے

میں سمجھتا ہوں کہ ون مین لنگوسٹک مائنورٹیز سے کام نہیں چلے گا۔ اس کو ختم کر کے پارلیمنٹ کی ڈیموکریٹک سیکولر پارٹیوں کے کم سے کم تین نمائندے لے کر کمیشن کو بنایا جائے۔ جس طرح سے ایگریکلچرل پرائسز کمیشن ہے یا اور کمیشن ہیں اس طرح کا یہ کمیشن بنایا جائے۔ اس میں ریٹائرڈ ایم۔پی نہ ہوں۔ لیکن جو ایم پی چن کر آئیں انکو لیا جائے۔ وہ سٹیٹس میں جائیں اور جا کر وہاں ہو رہی ناانصافیوں کو دیکھیں اور یہاں پارلیمنٹ میں ان کو بیان کریں۔ ان کے نوٹس میں ان کو لائیں۔ اب بھی وقت ہے سرکار ان ناانصافیوں کو دور کرے۔ سب سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ کی جو ٹیریٹریز ہیں اس کے جو علاقے ہیں وہاں پر لنگوسٹک مائنورٹیز کو ان کے پورے رائٹس دیئے جائیں۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر سب سے پہلے دلی میں اردو کو دوسری

سرکاری زبان ڈیکلیئر کیا جائیں۔ اردو زبان یہاں پڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن کتابیں غائب ہیں۔ دلی میں ٹیکس بوک میشنلائزڈ ہیں کوئی اور ان کو چھاپ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اتنی تھوڑی تعداد میں یہاں ان کو چھاپا گیا ہے کہ اردو پڑھنے والے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں میسر نہیں ہوتی ہیں۔

یہ سٹیٹس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں جو ناانصافیاں ابھی تک ہوئی ہیں ان کو جاری نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ ڈیپارٹمنٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر کو اس بارے میں الگ اور بیکار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سرکار ان ناانصافیوں کو دور کرنے کے لئے قدم اٹھائے گی۔

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषायी अल्पसंख्यकों के कमिश्नर की 11 रिपोर्टें निकल चुकी हैं और उनके माध्यम से सारी स्थिति सरकार के सामने आ चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार ने कोई साहसपूर्ण कदम नहीं उठाया है। आज कमिश्नर यह मांग करता है कि उसका स्टाफ बढ़ाया जाये। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन तेईस सालों के बाद अब सरकार क्या चाहती है। स्टेट्स री-आर्गनाइजेशन एक्ट के द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्य बनाये गये। अब सरकार एक नया सवाल पैदा करना चाहती है। भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में न तो केन्द्रीय सरकार कभी गम्भीरता से विचार करती है और न राज्य सरकारें। सरकार तो केवल यह चाहती है कि कमिश्न बना रहे, लेकिन वह उसकी रिपोर्टों को सिरियसली नहीं ले रही है।

आज संसार इतना छोटा हो गया है। लोग चाहते हैं कि वे अन्य क्षेत्रों में जा कर वसें और विज्ञान, व्यापार आदि सब क्षेत्रों में प्रगति करें। लेकिन सरकार इन छोटी-छोटी भाषाओं के मामले को ले कर एक नई समस्या खड़ी करना चाहती है। इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि कोई भी राज्य सरकार इस बारे में सीरियस नहीं है। कई बार इस आशय को इंस्ट्रक्शन्ज दी गई हैं कि इन भाषाओं की किताबें और शिक्षक तैयार किये जायें। लेकिन आज स्थिति यह है कि न तो इन भाषाओं की किताबें उपलब्ध हैं और न ही शिक्षक मिल रहे हैं।

इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 24 से 28 में कहा गया है :

Madhya Pradesh which had hitherto restricted the facilities to the 15 languages specified in the 8th Schedule of the Constitution, have now provided facilities for instruction through Madia, a tribal dialect.

In Haryana, the State Government have now issued orders for imparting instruction through the medium of Punjabi in private schools.

In Maharashtra, the State Government have now issued orders to provide facilities according to the formula of 10/40 pupils throughout the State.

In the case of the Union Territories, Dadra and Nagar Haveli have now accepted the formula of 10/40 pupils.

With regard to maintenance of advance registers, no report has yet been received from the Nagaland Government indicating whether they have accepted the suggestion to maintain advance registers for linguistic minority pupils. In the case of the Union Territories, Chandigarh ; Goa, Daman and Diu ; Manipur ; and Pondicherry have also

[श्री मूलचन्द डागा]

not issued orders for maintenance of advance registers.

जैसा कि मैंने कहा है, इस बारे में न तो केन्द्रीय सरकार सीरियस है और न कोई राज्य सरकार ही सीरियस है। चीफ मिनिस्टर्ज और सैंट्रल मिनिस्टर्ज ने एक स्टेटमेंट में यह राय जाहिर की थी :

It must be remembered that languages, if they are to be known at all well, must be learnt at an early age when it is easy for the child to pick them up. Therefore, both Hindi and English should be taught at an early stage.

राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों ने यह सलाह दी है, लेकिन कमिश्नर कहता है कि उस का स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए। कमिश्नर के पास काम नहीं है। वह शायद एक घंटा रोज काम करता होगा। इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि कोई राज्य सरकार कमिश्नर की इंस्ट्रक्शन्ज को फालो नहीं करती है और किसी राज्य सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। सरकार जबर्दस्ती भाषायी अल्पसंख्यकों के मामले को चला रही है। आखिर तेईस सालों के बाद इस प्रश्न की जरूरत क्यों पैदा हुई है ? कुछ भाषायें ऐसी होती हैं, जिन में धार्मिक किताबें लिखी होती हैं। लोग उनको पढ़ते हैं और संविधान में इसके के लिए कोई मनाही नहीं है। आज तक किसी वर्ग ने संविधान के आर्टिकल 347 के अंतर्गत अपनी भाषा की रेकगनीशन की मांग नहीं की है। सरकार क्यों ख्वाह-मख्वाह इस मामले को जारी रखे हुए है ?

कमिश्नर ने मांग की है कि उसके स्टाफ को बढ़ाया जाये। सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए। कमिश्नर की 11 रिपोर्टें आ चुकी हैं। अब उसकी 12वीं रिपोर्ट पबलिश नहीं होनी चाहिये। अब इस चैप्टर को सदा के लिए क्लोज कर देना चाहिए।

इस रिपोर्ट में कहा गया है :

"While, therefore, the office of the Commissioner for Linguistic Minorities is not the administrative machinery for implementation of the safeguards for linguistic minorities at the Central level, in the discharge of the statutory obligations, the Commissioner is to seek information from the Union Government and the Governments in the States and Union territories."

लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरीटरी ने इत्तिला नहीं भेजी है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर्ज की मीटिंग्ज 1949 और 196 में हुई हैं। बार-बार कई मीटिंग्ज होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बारे में एक बड़ी कांफरेंस में चीफ मिनिस्टरों और सेन्ट्रल मिनिस्टरों के अलावा पार्लियामेंट के मेम्बरों, एजूकेशनिस्ट्स और साइंटिस्ट्स वगैरह को बुलाया जाना चाहिए। कमिश्नर ने अपने काम के बारे में लिखा है :

"take extensive tours or investigation of grievances reported, and persuade State Governments and Union territories to implement fully the scheme of safeguards. In this task, the commissioner is assisted by two class I officers, one class II officer and a small team of eight ministerial staff. There are no regional offices. A proposal for the strengthening of the staff is under consideration of the Government of India."

गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस नहीं है। उस ने आज तक एक भी डिसिजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वह एक औपचारिकता को निभाने के लिए मीटिंग करती है, उस में निर्णय लिये जाते हैं और कमिश्नर उस मीटिंग में आकर बैठ जाता है।

जब कमिश्नर जयपुर में गया, तो उसने लैंग्वेज प्राबलम को नहीं लिया बल्कि उसने एक नई प्राबलम खड़ी कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है :

"During the Commissioner's visit to Jaipur in 1969, the president of the

Akhil Bharatiya Sindhu Seva Sangh complained that the Sindhu Seva Sangh pilgrims' party was not permitted to visit the Sadhubela shrine in Sukhkur in Pakistan."

उसने लैंग्वेज के सवाल को छोड़ दिया और एक दूसरे सवाल को ले लिया, जो उसके जूरिसडिक्शन में नहीं था।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Sindhi is a regional language now.

श्री मूलचन्द डागा : इसमें पिलग्रेमेज का सवाल कैसे पैदा होता है ? क्या यह सवाल कमिश्नर के जूरिसडिक्शन में था ? कमिश्नर का काम लैंग्वेज और कल्चर से सम्बन्ध रखता है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिये उसने यह सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सवाल उसके स्कोप में था ? इस बारे में रिपोर्ट में क्या कहा गया था ? रिपोर्ट में कहा गया है :

"The Pakistan Government, it is learnt, have refused permission, and the Government of India have since lodged a protest with the Pakistan Government, reminding them of their obligations to provide facilities to such pilgrim parties."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसने इस बारे में एनक्वायरी क्यों की। उसका काम तो विभिन्न वर्गों की भाषाओं से सम्बन्धित है।

आर्टिकल 347 के अधीन किसी लैंग्वेज की रेकगनीशन के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है :

"Article 347 of the Constitution whereby the President may issue instructions for recognition of a minority language as official language in a State has not been invoked so far."

इसका अर्थ यह है कि 1951 से 1971 तक प्रैजिडेंट ने किसी भी लैंग्वेज को आफिशल लैंग्वेज के रूप में रेकगनाइज करने का डिक्लेरेशन नहीं किया है। सरकार ने अल्पसंख्यकों की भाषाओं के लिए एक कमिश्नर बना दिया है, लेकिन कोई उन भाषाओं को पढ़ना नहीं चाहता है। सब हिन्दी या इंगलिश आदि आफिशल लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं। सरकार के पास इन भाषाओं के न टीचर हैं और न किताबें। आप जानबूझ करके कोई दस लड़के कहीं मिलेंगे तो कहेंगे यह इस भाषा को पढ़ना चाहते हैं। अब एक-एक लड़का क्या अलग-अलग भाषा पढ़ेगा ? अल्प-संख्यकों का सवाल लाकर आप समझते हैं कि बड़ी उनकी इससे रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है। अंग्रेजी और हिन्दी यह दो भाषायें आफिशियल लैंग्वेजेज हैं। यह पढ़ें हिंदी पढ़ें तो वह कुछ काम कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि उड़िया पढाओ जब कि खुद अंग्रेजी में बोलेंगे। दे विल स्पीक इन इंगलिश और उड़िया की वकालत करेंगे। आपने खुद तो अंग्रेजी पढ़ ली और दूसरों को कहेंगे कि तुम उड़िया पढ़ो।...(व्यवधान)...कहीं कहेंगे कि भोजपुरी पढ़ाओ, कहीं मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि हमारे यहां की आदिवासियों की भाषा पढ़ाई जाय। हमारा इन लोगों से यह कहना है कि क्या आप खुद उन भाषाओं का उपयोग करते हैं ? उनको तो आप कहेंगे कि रीजनल लैंग्वेज जो उस क्षेत्र की है उसी तक सीमित रहो और अपने पढ़ेंगे अंग्रेजी। तो अल्पसंख्यकों का सवाल लेकर 23 साल के बाद आपकी यह रिपोर्ट आती है भाषाओं के ऊपर, यह बात कुछ मेरे दिमाग में बैठती नहीं है। गवर्नमेंट को कोई साहसपूर्ण कदम उठानी चाहिए लेकिन गवर्नमेंट देखती है कि चलो कि जैसे चल रहा है चलने दो, परम्परा जो चली आ रही है उसे चलाए जाओ। एक कमीशन बना दिया, उसने एक रिपोर्ट पेश कर दी। होम मिनिस्टर का एक पोर्टफोलियो इसका बना दिया। लेकिन न तो इसको सीरियसली कभी थिंक किया और न इस बारे में कोई कार्य हुआ। मैंने रिपोर्ट को देखा है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ठीक हैं। कोई

[श्री मूलचन्द डागा]

सीरियस कंसीडरेशन नहीं है । कोई लड़का पढ़ता है, सिंधी में कोई धर्मग्रन्थ है उसे पढ़ना चाहता है तो उसे मना कौन करता हैं ? और खुद वह भाषा बोलना नहीं चाहते हैं, खुद तो हिंदुस्तान में अंग्रेजी चलाना चाहते हैं और उनके लिए कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज पढ़ाओ आज यूनिवर्सिटीज के अन्दर यह सवाल है । क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लड़के यूनिवर्सिटीज में आयें । यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का तो हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ेगा । वहां उसकी यह लैंग्वेज तो चलेगी नहीं । तो यह जो बात है यह कुछ समझ में नहीं आती । अब 23 साल के बाद कल एक माननीय सदस्य कहने लगे कि कोर्ट में आदिवासी आते हैं तो भाषा नहीं समझते हैं । मैं कहता हूं कि अच्छी तरह समझते हैं आज वह काफी आगे बढ़ चुके हैं ।...

श्री आर० वी० वड़े (खरगोन) : आप राजस्थानी की मांग नहीं करते ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं मैं नहीं करता । मैं तो कहता हूं कि हिन्दी भाषा है, ठीक है । मैं छोटी-छोटी भाषाओं के पक्ष में नहीं हूं । और 23 साल के बाद यह आपके कमिश्नर की 11वीं रिपोर्ट पढ़ने के बाद यही देखने को मिलता है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने या प्रान्तीय सरकारों ने कभी भी सीरियसली इस पर थिंक नहीं किया । अगर किया हो तो बतायें । आज यह तीन भाषायें चाहते हैं । तमिलनाडु में हिन्दी अंग्रेजी और एक वहां की भाषा तीन भाषा चाहते हैं । श्री लैंग्वेज का फारमूला चाहते हैं सभी जगह । तो क्या आप गांव वालों को चार लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं ? उनके लिए आप चार लैंग्वेज का फारमूला चलाना चाहते हैं ? तो यह जो आप प्रोटैक्शन देना चाहते हैं आज 23 साल के बाद इसकी जरूरत नहीं है । यह अल्पसंख्यकों का कोई सवाल नहीं है । आज भाषा पढ़ने वाले मुश्किल से 39 परसेंट लोग हैं बल्कि उससे भी कम हैं । तो यह तो एक बहाना मात्र है । कुछ लोग धर्म के नाम पर मदरसा खोलना चाहते हैं तो खोलें, पढ़ें, उसमें संविधान मना नहीं करता । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल उपयोगी चीज नहीं है । इसको खत्म करना चाहिए ।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : This country is a rich tapestry where various languages and cultures are so nicely interwoven as to make it a beautiful home. It is a combination of varieties of cultures and languages and this diversity constitutes the richness of this country. Their preservation and promotion is the responsibility of any civilised government.

If you look at a big country like the USSR, it is a federation of autonomous states carved on the basis of culture and languages.

Sir, I do not agree that this diversity of culture and language will stand in the way of national or emotional integration. Unity in diversity is the characteristic of this country and if we deny justice, if we deny them the rightful place in the national life of this country, if we fail to look after them, if we subject them to the tyranny of the majority, as suggested by the previous speaker, then, with eyes wide open, let them have a look at Bangla Desh. I am grateful to the DMK movement against the imposition of Hindi there. They had to bow to the wishes of the people of Tamil Nadu. I take my hats off for them.

This language is such an emotional tie, and the mother-tongue is the first word which comes out from the mouth of the mother to the child; it is such an emotional tie which keeps them binding together. If we go further to the genesis of this national movement, you will see that the entire national movement gathered momentum at the partition of Bengal. This "Banga-Bhanga" movement is responsible for bringing in the national movement to this stage. Even during the national movement, it was the main plank of the national movement to form the States on the basis of language. As I said earlier, language and culture are so interwoven that wherever you draw the line, there would be minorities. We cannot have watertight compartments.

And to look after them and safeguard their interests is the responsibility of the Government of the State concerned.

Taking cognizence of the gravity of the situation, those who framed the Constitution had provided specific provisions in the Constitution. Articles 29, 30, 350A and 350B are special constitutional safeguards for the minorities. Articles 29 and 13 which have been enumerated in Chapter III fundamental rights—have become piecrusts ; they can be broken at the convenience or at the sweet will of Parliament.

After Independence, the States Reorganisation Commission was appointed under Justice Fazl Ali who was a former Governor of my State—Orissa, He gave a hurried report. There were various lacunae and that is why there was widespread resentment and so much of bloodshed, and at last the Government was forced to yield to the demands of the Maharashtra Samiti and the Mahagujarat Janta Parishad and had to split the bilingual State of Bombay into Maharashtra and Gujarat. The Punjabi Suba was achieved only by the efforts of the people of the area. The Fazl Ali Commission never recommended it. You, Sir, got your Meghalaya because you could assert yourself and because you could make your voice felt by the nation, that it was a necessity. Similarly, Seraikella and Kharaswan, which were predominantly Oriya tracts, which form an Oriya island in the Bihar sea, as it were, which were contiguous to Orissa, were denied to us. Up till now, the same tyranny and torture go on. There is discrimination in getting jobs and there is no facility of education in the primary stage. Various complaints have been brought to the notice of Parliament by this report.

Sir, this report further says that in respect of Seraikella and Kharaswan, so far as Bihar is concerned, the Commission asked for statistical data from the Bihar Government regarding the educational facilities for the minorities. That is in para 133.

But the Commission has stated that the Bihar Government never complied with that request. You will be surprised to find that efforts have been made to completely liquidate the Oriya culture and language in that part of the country. Dirty politics has entered into the Chou dance which is a famous dance there. Similarly, a country liquor shop has been planted just in front of the girls' primary school in Seraikalla to shop its functioning. We are getting such reports. It is a wild cry in this Parliament because we know that the Central Government will plead its imbecility, impotence and complacency ; they could not deliver the goods ; they pass on the buck to the State Government that they will do : we are helpless ; what can we do ? Similarly in Andhra Pradesh, the Oriya minorities are not getting their school teachers and the Government forms in Oriya are not available to them. Even in the Registrar's office there is no oriya clerk. Similarly in the Raipur, Raigarh and Bastar districts of Madhya Pradesh which border on Orissa, there is a large concentration of Oriya population and they had been subjected to the same tyranny.

When so many difficulties have been pointed out and have been rectified after the SRC report, I cannot understand why so many boundary disputes have come to the forefront. Why not have a permanent solution to it ? The Mahajan Commission was appointed to go into the question of Mysore-Maharashtra dispute. I am sorry to say that inspite of the recommendations of the Mahajan Commission, the whole thing has been hanging fire for so long because the issue has to be decided on a political plane, according to the election prospects of the party in power. Most emphatically I make a demand that the recommendations of these commissions should be considered as awards. The decision on the Mahajan Commission report on the Mysore Maharashtra border dispute has been, I came to know, left to the sweet will of the Prime Minister to be taken at her convenience as it suits the party in power.

So far as Maithili is concerned, I was inspired to speak about it by my friend Mr. K. N. Tiwari who is there. I was a student in Patna and that language is so rich that right from the days of Vidyapathi till today there is such a vast collection of literature. There is even a post-graduate study of this language in Bihar, in the Patna university. Till how it has not been recognised as a regional language.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah): It has been recognised now.

SHRI P. K. DEO : It makes painful reading. It is a futile exercise. I do not

[Shri P. K. Deo]

think any useful purpose would be served in wasting the time of the House on a debate like this. For God's sake you wind up this shop of linguistic minorities commissioner and do not provide a cushion for defeated politicians. It will serve absolutely no useful purpose. If you are keen about it, take courage in both hands and look after the interests of the minorities so that they could be saved from the tyranny of the brute majority. We do not want the law of the jungle to rule here, the right of might.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझसे पहले बोलने वाले राजा-साहब ने शायद इस की इम्पोर्टेन्स को, इसकी अहमियत को नहीं समझा...

श्री पी० के० देव : पंजाबी सूबे के लिए तारीफ़ की है।

श्री दरबारा सिंह : पंजाबी सूबा आप की कृपा से जो बना है, वह कितना लंगड़ा-लूला है, वह बाद में कहूँगा, लेकिन जो मैं इस वक्त अर्ज करने वाला हूं, वह यह है कि यह जो रिपोर्ट है, यह कमिश्नर की तरफ से बड़ी अानेस्ट-एफर्ट है। यह कहना कि इसकी इम्प-लीमेंटेशन सरकारी सतह पर कितनी हुई है या नहीं हुई है, यह अलेहदा बात है, लेकिन इस में दो रायें नहीं हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है, स्टेट्स में जो फैक्चुअल पिक्चर एक्जिस्ट करती है, उसका जिक्र किया है, उसको साफ-गोई से रखा गया है। इस को ऐसे ही थी-आउट करने की जरूरत नहीं थी। यह कहना कि यह दुकान बन्द कर दी जाय, दुकानें तो और भी बहुत-सी बन्द करने वाली हैं, आप की दुकान भी बन्द होने वाली है, लेकिन ऐसे ही इस दुकान को बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि यह माइनौरिटीज का सवाल है।...

श्री पी० के० देव : आप तो मोनोपोलिस्ट्स हैं।

श्री दरबारा सिंह : ठीक है, हम अपने आपको इसलिए जरूर मोनोपोलिस्ट मानते हैं कि आप जैसे दोस्त, जो दौलत पर सांप बन कर बैठे हुए थे, उनको नीचे खींच लिया गया है।

इस रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। मैं एक बात मानता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट-सरकारों की सतह पर कुछ नहीं हुआ है इसलिए भारत सरकार को चाहिये कि इसकी तरफ खास तवज्जह दे ताकि जो फैसले हुए हैं उनको सही तरीके से लागू किया जा सके, आज इतना भी नहीं हो रहा है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, इस में पंजाब के बारे में एक चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको कोई फिगर्स सप्लाई नहीं की यह भी नहीं बतलाया कि कितने लड़के माइ-नौरिटीज के पढ़ते हैं, कहां पर वह माइनौरि-टीज को मानते हैं कहां नहीं मानते हैं। लिंग्विस्टिक सूबा तो बन गया लेकिन कोई भी बताने वाला नहीं है। आज लिंग्विस्टिक माइ-नौरिटीज को धर्म और मजहब के नाम से जोड़ दिया जाय मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अगर कोई लैंग्वेज पढ़ता हूं, तो इस ख्याल से नहीं पढता हूं कि वह मेरे धर्म की लैंग्वेज है बल्कि इस ख्याल से पढ़ता हूं कि वह मेरी स्पोकन लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को कौन पढ़ता है, कितने लोग पढ़ते हैं, उसका सही इन्तजाम होना चाहिये।

आजादी से पहले उर्दू सारे पंजाब की जुबान थी, जब हम अलहदा हुये तो पाकिस्तान ने उसको अपनी जुबान बना लिया हालांकि उर्दू उनकी जुबान नहीं है उनके यहां कहां से आई, वह तो हमारी जुबान थी। पंजाब यूनी-लिंगुअल स्टेट बन गया है, लेकिन वहां क्या हुआ, मैं अभी उसका जिक्र करने वाला नहीं हूं क्योंकि वह पोलिटिकल ईशू है। उससे कितने

लोगों को तकलीफ हुई है, कितनी अन-सर्टेन्टी उससे पैदा हुई है, पजाब का कितना नुकसान हुआ है, पडोसियों का कितना नुकसान हुआ है, मैं इसके बारे मे जिक्र करनेवाला नही हू, लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि जुबान का जो ममला है, जो माइनौरिटीज का सवाल है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ।

पजाब के बारे मे मैंने इस रिपोर्ट मे जो पढ़ा, उससे मालूम होता है कि सरकारे-हिंद को उन्होने कोई चीज दी ही नही और अब जब आबादी का हिसाब लगाया तो उन्होने कहा कि 1 करोड़ 1। लाख 35 हजार 5। है । देखिए, कितनी प्राम्पलेम मे वह काम करते है—वहा पर अकालियो की सरकार थी—उन्होने कहा कि यह जो आबादी है, इसमे किस की शमूलियत है, होशियारपुर जिले की ऊना तहसील का जो हिस्सा चला गया है वह भी इस मे शामिल है, सगरूर का हिस्सा भी इसमे है अब आप ही बतलाइये, वह कैसे कह सकेगे कि यहा इतने बच्चे उर्दू पढनेवाले है, या दूसरी जुबान पढनेवाले है । इसको हमारे यहा "घपला" कहते है एक तरह का कन्फयूजन है । इसमे इतना कन्फयूजन कर दिया गया है कि हिंद सरकार के पास सही रिपोर्ट नही आ सकती इसलिए इसके इम्पलीमेंटेशन के लिये सरकार कौन से जराये अख्तियार करना चाहती है, इसकी तरफ तवज्जह देने की जरूरत है ।

इस रिपोर्ट मे बहुत सी बाते हैं, सच्चर फार्मूले का जिक्र आया, बहुत लम्बी-चौडी बाते हैं कोई-सा सफा उठाकर देख लीजिये पजाब का ही नही दूसरी स्टेटो का भी यही हाल है वे भी फिगर्स देने के लिए तैयार नही है । एक कमेटी बनी थी—कमेटी आफ जोनल कौन्सिल उसमे यह फैसला हुआ था—नो-स्टेट इज यूनिलिंगुअल । मुझे पता नही कब फैसला किया । और फिर कहते है यूनिलिंगुअल नही है अगर यूनिलिंगुअल नही है तो उन तमाम जबानों को जो माइनारिटीज की हैं हर जगह पर गुंजायश की जा रही है या नहीं—इसके बारे मे मुझे कंफ्यूजन है और इसको साफ करने की जरूरत है ।

इसके साथ-साथ मैं कहता हू कि नेशनल इटिग्रेशन की बहुत जरूरत है । हमारे दोस्त डागा साहब ने कहा है कि ऐसी चीजों की जरूरत नही है लकिन मैं कहता हू इट इज ए फैक्ट आफ लाइफ । हमारे कान्स्टीट्यूशन में प्राविजन हैं और उसके मुताबिक यह सब किया जा रहा है । इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाये और जितनी माइनारिटीज हैं उनका तहफ्फुज किया जा सके इसके लिए कम से कम जो उनकी जबान है वह न हजफ कर दी जाये। इसके लिये एक उपाय किया गया है, प्रबन्ध किया गया है मेजर्स लिए गए हैं । लेकिन मै इसके साथ साथ कहना चाहता हू कि सेन्टर की तरफ से एजूकेशनल सिस्टम को तब्दील करने की जो बात है और जो इटिग्रेशन की बात है उसमे किसी जबान को दुरुस्त करके हजफ करके जो हम करना चाहते है उसमे न उनको कोई आराम होगा और न उनका तहफ्फुज होगा । मै मानता हू कि आप नेशनल इटिग्रेशन मे लगे हुए है लेकिन एजूकेशन सिस्टम मे क्या है ? वह पढाते है जो नही पढाना चाहिये और जो पढाना चाहिए वह नही है । इसलिए एजूकेशन सिस्टम को तब्दील करना होगा । स्टेट लेविल पर जो किताबें निकाली जा रही है उनकी भी क्या हालत है ? इस बारे मे बहुत न कहकर यही कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई यूटिलिटी इसकी हो तो यूटिलिटी तभी हो सकती है जब इसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ जराये अख्तियार किए जाये । जब तक यह नही होगा तबतक रिपोर्ट आती जायेगी और हमे पता चलता जायेगा कि कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है पर देख लेना, मै आज कहता हूं कि अगली रिपोर्ट भी ऐसी ही होगी । मैं यू० पी० वालों और बिहार वालों की बात मानता हूं और अर्ज करता हूं कि वहां पर उर्दू को गुजा

[श्री दरबारा सिंह]

यह देनी चाहिए। सब पार्टीज की यही राय है और सभी लोग चाहते हैं कि जहां गुंजायश हो सकती है वहां उनको देना चाहिये और नेशनहुड का जो सबक है उसको लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो लोकल लैंग्वेजेज हैं जो माइनारिटीज की लैंग्वेजेज हैं उनका लिट्रेचर भरा पड़ा है क्योंकि इसके बिना हम इंडिपेन्डेन्स की लड़ाई लड़ नहीं सकते थे। जजबात को उभारने के लिये जो खयालात होने हैं वह उनमें मिलते हैं। इसलिए जबान को खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि इंटिग्रेट किया जा सकता है। इंटिग्रेशन बहुत जरूरी है इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसका इम्प्लीमेन्टेशन अगर स्टेट लेविल पर करवा सकते हैं तो ठीक है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसको वे करते हैं लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जो इसको नहीं मानती। हरियाणा वालों ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कह दिया कि उर्दू को मानते हैं पंजाबी को मानते है और अगर कुछ लड़के पढ़ने के लिए आ जाये तो उनको गुंजायश देंगे। ऐसा हिमाचल वालों ने भी किया है। और भी जगह ऐसा होना चाहिए ताकि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के दिल में यह बात पैदा न हो कि हमारे साथ सुलूक ठीक नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। तब हमारा काम बन जायेगा। इन अलफाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

PROF NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) Sir, the Eleventh Report of the Cammissioner for Linguistic Minorities brings to our view certain important factors and certain facts of life, which are present on the Indian scene I have gone through some of the important sections of this report and I am happy that there are facilities for the teaching of the languages of the minorities. I for one do not agree with the views expressed by Mr, Daga and our friend from the Swatantra Party that the commission should be wound up and the Commissioner's office is a useless office

I think those who say such things have no idea of what a language is Language is not the handmaid of religion, it is neither the handmaid of politics nor is it the handmaid in the hands of a clerk or an IAS officer It is the rich expression of the emotions of a culture which is still living If we are trying to throttle the linguistic minorities or the languages which they perfer to use in their daily life, we are committing a grave blunder I think it would be a sad day for India when we declare that India is a unilingual country and only one language can flourish in India The fact of life is that India is a multi lingual country So, we must recognise the beauties of Tamil literature, Urdu literature, English literature and for the matter of that the literature written in French by Aurobindo Ghosh and so on India must open its doors and windows to the outside world We must preserve the plants and flowers (languages) that have grown on Indian soil for ages past.

I have noted with interest some of the failures by the State Governments to rise to the occasion which have been mentioned by the Commission I am rather shocked at the disclosure that the Bihar Government has not thought it fit to publish pamphlets dealing with the safeguards availabe to the minorities The same treatment has been meted out to the minorities in Punjab

So far as the languages of the minorities are concerned the Report covers three aspects The first aspect is the availability of facilities for teaching these languages. The second aspect is official declaration of official languages of the States and the place or status given to the languages spoken by the minorities The third aspect is recruitment to the services On all these three scores the States have failed It would not be proper to throttle the people that cry If the Commissioner for Linguistic Minorities brings to our notice certain failures, it should be our endeavour and the endeavour of the government at the Centre to rectify those errors, to remove th causes that are responsible for those grievances. I think the Commissioner is doing a useful service by pointing out to us certain dark spots in our educational scene.

Although it has been written in the very first few pages, page 6 for example, that the States are alive to this, what follows is a sad story that the States are not alive to this. I am reminded of a very interesting incident that I read in the press of Punjab some time back. A lady lecturer of the Government College for Women in Amritsar applied for the post of the Head of the Department of Zoology to the Punjab Public Service Commission. But they refused to acknowledge her claims because the lecturer in zoology could not pass a test in Punjabi. Now I cannot understand how knowledge of Punjabi is important or essential for subjects like zoology or botany or for technical services. In order to provide safeguards for the services, we must not insist on knowledge of the regional language. It is another matter that we may regard it as desirable and a person can be asked to learn it after he or she has been recruited.

SHRI K. MANOHARAN (Madras North) : Was the insistence on working knowledge or degree or something ?

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : She was given a test in Gurumukhi which she could not pass. So, her junior was promoted and she was not considered for the post. The assurances that have been given in this report about the safeguards that have been provided to the linguistic minorities are useless in the face of these blatant violations, because these safeguards are not available to them. I do not want to go into the merits of this case because it is at present pending in the Punjab High Court.

I would like to point out here that wherever such injustice exists we must fight it out. Safeguarding the interests of the minorities is not the concern of only one State or another State—it is the concern of the whole of India. It is not a question of Panjabi versus Hindi, or Tamil versus Malayalam or Pahadi versus Dogri or anything of that type. It is a question of restoring justice. A citizen of India has every right to stay wherever he likes and yet study in his own mother tongue.

15.00 hrs.

People think that if India is a unilingual country, all the problems will be solved. I think, the problems will not be solved ; they will be multiplied beyond any cure. We must not insist on such a diabolical design but we must fight it with all the might at our command.

It is right that in a democracy there is a cell or a commissioner's office for looking to the rights of minorities and that these things are available for our review in Parliament and we are able to raise our voice. In a dictatorship or a theocratic state like Pakistan, it will not be possible to raise our voice in such a manner. To those friends who are demanding the winding up of this establishment or the closure of this commissiner's office . . . (*Interruptions*)

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : मैं आप की व्यवस्था चाहता, हूं इतना सुन्दर भाषण हो रहा हैं और सदन में गणपूर्ति भी नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The bell is being rung. . . Now there is quorum. He may continue his speech.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : I was referring to the demand made by certain Members to close down this Commission. I think, we are determined and should be determined to fight such a demand and should never allow it to be accepted.

So far as the languages of the minorities are concerned, there are certain inherent difficulties because generally people think that if there is an official language there is no need for any regional language. But this is something which is unscientific. We must recognise that the Tribals, who are living in the jungles, also have a language of their own. I am happy to learn from this report that there are certain provisions made in the schools of Madhya Pradesh fer a language like Madia and others and certain textbooks are also being provided. But there are some other difficulties ; for example, the dearth of teachers. The report says that there are no qualified teachers of Sindhi and Urdu in Rajasthan, Oriya in Andhra Pradesh and Kannada in Kerala. In other provinces similar deficiencies and drawbacks exist. So, it must be our endeavour to have a coordinated programme.

I think, this Commissioner for Linguistic

[Prof. Narain Chand Parashar]

Minorities should have a larger office and each State should have a unit of its own—a small office under the supervision of this larger body—and they should coordinate their activities with the State Department of Education. The Union Ministry of Education should also look to it that trained teachers are available and are provided to them.

Then, there is the problem of textbooks for a small number of speakers. A large number of speakers are of Hindi and a few speakers might be speaking the Tribal language. They do not get encouragement because there are not enough textbooks, not even teachers. So, it should be our endeavour to provide textbooks on an all-India basis for these languages and dialects.

Certain people confuse the question of a language with a script. I think that is not proper, because there are languages which have many scripts and there are certain scripts which are used for more than one language. Kamal Ataturk in Turkey decided in 1928 that the Turkish language shall be written in the Roman script. The language has not lost its beauty nor has the literature lost its fragrance because it is written in the Roman script. So, the languages or India can be written in one script to another. That does not matter. It should be left to the choice of the readers and the speakers. They can choose the script which is useful for them.

The report also mentions some sort of incentives which are being provided, like advance increments and cash grants for teachers of these languages. I think, this is a useful step which must be encouraged.

Then, there is a very interesting institution, a useful one, in our country, namely, the Central Institute of Languages in Manas Gangotri in Mysore. I had an opportunity of visiting this institution only last month and I was shocked that a Committee of the Secretaries of the Government of India took a decision to suspend the publication of a magazine called *Vartavaha* which was being brought out there and which gave on integrated picture of what was happening in various linguistic fields of India, in Punjabi, in Assamese, in Tamil, etc. I do not know how that decision was justified. I think, such a magazine which was the unique one should be allowed continue because, through the medium of English, we are able to know in Srinagar and in Shillong, in Trivandrum and in Delhi what is happening in various fields of knowledge. This will go a long way in making us understand the progress that has been made in various languages of India.

Then, there is a very interesting remark in the Commission's Report that there is a new trend and trend is that tribals and other minorities want to study their language as a subject of study a nd not as a medium of instruction. I think, even if we are able to do this much for a language of the tribals or a language of the minorities, if we cannot make it a medium of instruction but only provide facilities for making it as a subject of study, that is also welcome. So, whatever facility is provided for the study of languages at various levels should be welcome. I hope, this will be done.

There is one thing that we must do. A language should not be left to the mercy of a few individuals, whether they are IAS officers or they are people who are in the Commission or this and that. We must provide for a central agency of linguistic experts to find out and coordinate the progress made in various fields of Indian languages and what facilities are available for the study, teaching and suitability and, availability of resources and facilities for these languages at various levels. This must be brought to the notice of Parliament from time to time.

The Report is a very useful one. I am happy that certain safeguards have been provided for languages like Urdu which have been available for us in our freedom struggle and the inspiring songs and messages with which we were able to go to the star of freedom.

Also, there are certain languages which suffer from this problem that they are not spoken in one particular region. There are two such languages in particular, one is Sindhi and the other is Sanskrit. They must also be looked after. They should not be neglected because they are not spoken in one particular region but because they are spoken by a microscopic minority spreadover the whole of India. They should also be catered to and there should be greater importance to the role that they are going to play in our national life. I am happy that Sindhi has been included in the Eighth Schedule of the Constitution.

I come from a State where Urdu has been given due place. Himachal Pradesh has been able to give due place to Urdu and provide facilities for the teaching of Urdu right from the 3rd Class onwards at the primary stage. Similarly, there are provisions for the teaching of Punjabi and other languages. So far as our State is concerned, there is no problem of the minorities. But we have our own language *Puhari* and we would like to develop it. I would request the Central Government to see that developing languages are not given a suffocating touch at the very beginning of their life.

After all, the literatures of India, whether they grow in the mountains or on the sea-shores or near the coastal lines or in the valleys, they are our literatures and they must be looked after. The languages of minorities are our sacred heritage. We must do everything to preserve the fragrance and provide an opportunity for their flourishing at every stage and in every state.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very thankful to the hon. Members who have taken part in this debate and shown such a keen interest in the problem of linguistic minorities.

As I stated in my introductory remarks, there are various constitutional provisions regarding protection to be given to the linguistic minorities and the limited role that the Central Government can play in this regard. Not that the Central Government does not give due importance to this very important problem but it has to be accepted that the Commission of Linguistic Minorities ..

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। सदन में मंत्री जी का वक्तव्य हो रहा है और यहां पर गणपूर्ति नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The bell is being rung.

Now there is quorum The hon. Minister may continue.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : As I was saying, the Commissioner for Linguistic Minorities is a functionary that has been mentioned in the Constitution but he does not have executive powers in the sense in which the State Governments have with respect to teaching of languages and other concerned matters. It is really a very delicate question as to what extent we can take it up or press the State Governments for implementation of these various decisions. In this House itself we have heard on a number of occasions hon. Members saying that the Central Government is interfering too much in the affairs of the States and in matters which are essentially and constitutionally the legal responsibility of the States, but, when it comes to the implementation of many other decisions, and in this instance, the report of the Commissioner of Linguistic Minorities, again, a demand is made that no more attention is given to the implementation of these recommendations. So, the Government of India has a very delicate task in this matters and we have not been oblivious of our responsibility and the Commission has also taken very great pains An hon. Member said that the Commissioner hardly works for an hour or two a day. If he had carefully read this report, it would have come to his notice that the Commissioner made very extensive tours, visited many areas, heard a lot of representations from linguistic minority organisations, visited schools where minority langauges were being taught and took up the matter with the State authorities from the State Chief Ministers downwards. I have no hesitation in saying that the Commissioner has discharged her responsibility with great success and efficiency.

Various points have been raised, of which I will mention the more important ones. Some reference was made to teaching of languages which do not have a clear-cut script of their own. Mention was made about the teaching of Tripuri and of teaching of tribal languages in Madhya Pradesh and similar other tribal languages. Sir, it is true that these tribal languages are spoken by quite a large number of people in certain areas. But when it comes to implementing the decision regarding the linguistic minorities with respect to these languages, the difficulty arises because there is no definite script in which education at primary and secondary level can be imparted to these minorities.

Various States have adopted various expedients in this regard. Some of the tribal languages are being reorganised to

[Shri Ram Niwas Mirdha]

adopt scripts of the regional language. Some other dialects are adopting other scripts, and I think that some progress has been made in this respect. But this is a very difficult problem. Evolution of a language, particulary the script, and then the production of textbooks, and then the training and preparation of teachers to teach in those particular languages—these are all very difficult tasks, and I do not think that we can expect very spectacular results, particularly with regard to the tribal languages or dialects. But, as would be apparent from the report, in the various States, efforts are being made, and I think that some progress has been made, and I do hope that the State Governments would take more interest in these backward areas and backward communities and see that their languages are developed in the proper way so that proper education could be imparted through them.

Some hon. Members have gone to the extent of saying that the commissioner's office should be wound up. We even have a substitute motion in that respect. Shri M. C. Daga even went to the extent of saying that even the basis for teaching through these minority languages should be reconsidered. I think that these extreme views suggesting almost the same thing which means the abolition of the office of the commissioner arise from different motives. On the one side are Members who genuinely believe in the importance of linguistic minorities and the preparation of textbooks in those languages, and because they are not satisfied with the progress that has been made in this respect, they say that this post should be abolished. But I do not think that they really mean it when they say so, because the various suggestions that they have put forward imply that more and more power should be given to the commissioner, there should be regional commissioners, the staff of the commissioner should be strengthened and there should be more inspections, field visits and more supervision over implementation and so on. We shall take note of those suggestions and see that the organisation of the commissioner is strengthened and more inspections and field visits take place and greater coordination is established with the State Governments and greater implementation is ensured in this regard.

There are two languages, namely Urdu and Sindhi which do not have any region where they are spoken or used, and in that sense, they are not regional languages strictly speaking, but they have a constitutional status which entitles them to a very special consideration.

In regard to what has been said about the Urdu language here, we do accept that Urdu is one of the most important miniority languages in our country and that is the reason why Government have taken certain steps in regard to this language. In view of the special position that Urdu occupies as a linguistic minority language, Government have issued a special statement on the Urdu language dated July 14, 1958, which brings out what it expects the various State Governmets to do in this respect. The statement says that Urdu has a very special place in various cultural spheres and it is a language which is spoken almost all over the country and particularly in the northern States. In areas and regions where the Urdu language is prevalent we have suggested that certain facilities should be specially provided. I do not think that I need repeat them. Apart from facilities for teaching at the primary stage, it has been suggested that though the rules and regulations would not be translated, certain summaries of rules and regulations that are promulgated by the State Governments would be available in the Urdu languages in the particular areas where it is spoken.

Then there are certain areas where Urdu is being spoken. Representations to various government offices could also be received in that language in those areas. In this way, there are a lot of facilities that Urdu-speaking people will have, as mentioned in this.

It was mentioned here that all these facilities are not being given. To some extent, this is true. The facilities mentioned here are not being given in all the States on a uniform level. Government are constantly in touch with the various States Governments, particularly of UP and Bihar where quite a substantial percentage of the population speak Urdu. Every effort is made to see that the concessions listed in the statement on language of 1958 are made available to them. I am happy to say that because of the initiative taken by our Ministry and the personal interest evinced by the Prime Minister in this respect, some

results are coming and the Bihar and UP Governments are very much alive to the situation and are taking more interest and making more and more facilities available to them.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga) : What about the development of tribal languages ? Where do they stand ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I started with tribal languages.

SHRI R. V. BADE : Devnagari script can be used for the Adivasi language.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : In some states, the regional language script is used ; in others the Devnagari script is being used for tribal languages. Tribal languages are being developed in that respect. But I mentioned there are still certain areas where a clear-cut script has not come. Even where a script is evolved, textbooks are not available. Therefore, the problem of enforcing these in the tribal and border areas is very real, to which we are giving due attention.

To give the latest position, the UP Government has set up a Board of Urdu Studies. A post of Deputy Director for Urdu Educarion has been created. Efforts are being made for overcoming the shortage of text books. Arrangements are also being made that in districts where a substantial portion of the population is Urdu-speaking, people will have at least in one degree college arrangements for Urdu teaching. Similar steps have been commended to the Bihar Government.

The same thing about Sindhi which was also very recently given the status of an official language by a constitutional amendment. Sindhi is also being promoted in a number of areas. I mentioned special progrommes on the AIR recently introduced in Delhi. In addition, a number of regional stations give Sindhi programmes on a regular basis. There is the question as to whether the Sindhi script should be in Arabic or Devnagari Some States are using both according to the wish and desire of the local population. What I mean to say is that in spite of the script difficulty, progress is being made in Sindhi and more and more schools have started using Sindhi for teaching at the primary and other level.

I was very glad to hear what Shri Parashar said. He brought a great sense of realism and urgency to the discussion. Replying to critics, he said that there cannot be one language for the whole country. That was not the way in which we could have national integration. This was aptly said. Shri P. K. Deo said that ours is a country where various languages are spoken which have great cultural roots and the essential unity of the country is not detracted from by the cultural diversity we see around us.

Similarly, when Shri Parashar said that language should not be made the handmaid of religion or politics as is being sometimes made, I thought it was a very wise observation. I think if we all approach the problem of language in this spirit, it will be all the better for all of us and it will strengthen our national solidarity.

Shri Parashar mentioned about some magazine which is being published by the Central Institute of Indian Languages and also the need for a central agency where language teaching and linguistics in regard to various Indian languages should be given. These things do not belong to my Ministry ; they are the concern of the Ministry of Education and I will take it up with them and convey the suggestion and the viewpoints that the hon. Member has made in this matter, and I am sure they will give it due consideration.

Shri Parashar also mentioned about a lady lecturer in biology being not selected because she did not know Punjabi. As you would see, in the present decision, it is said that when recruitment is made to the State services, knowledge of local language should not be insisted upon. Actually, if any State does so, it is against this decision. In recruitment to the State services, the State Government language should not be a bar. The test of proficiency in the State official language should be held after selection and before the end of probation. This decision says that the regional language could be insisted upon but not at the time of recruitment. And Punjab did have a rule of that type that the hon. Member mentioned, but it has recently been amended which means that it would be no bar to the selection of a candidate, but the person who is selected, will have to learn Punjabi within a certain period after he joins duty. It does not go as far as to say that it should be "before the end of probation," but it

[Shri Ram Niwas Mirdha]

meets the objection that the hon. Member has raised, and I do not think any more complaint would arise so far as this aspect is concerned.

I would end by saying again that the role that the Central Government can play in this respect is of a very limited constitutional nature. But with the limited staff that the Commission has, I make bold to say that they have discharged their duty in a very admirable manner and the suggestions have come for strengthening this.

Shri Ishaque Sambali went to the extent of saying that there should be a three-member Commission and there were other suggestions that regional commission should be set up in various areas with greater staff. We will take all these things into consideration and really strengthen the Commission's working so that more could be done

I wish we could give a detailed and concrete report but the main executive authority is the various States Governments. But I do not think that makes this Commission helpless or important as one hon. Member put it. After all, the democratic process involves discussions ; it involves persuasion, and conferences and meetings, and I do not think we should be so pessimistic if the results are not as quick as we sometimes want them to be. But the results that come out of the discussion or after convincing the State Governments are much more stable, and I am sure that the State Governments also realise the importance. State Governments have regional languages of their own ; they will have people speaking that language and living in other States, and they would certainly wish that people belonging to the minority languages in those areas also get the same facility. So, it is in the interests of the State Governments themselves that the linguistics minorities should be given due production and due recognition because their own language.speaking people in other States also deserve and desire the same type of facilities.

I cannot say that the State Governments are not co-operating. They are co-operating, and if I had the time, I would give the figures to show how the number of schools in different States has increased ; the number of pupils and the number of teachers in minority languages has increased. The progress is there ; it is quite perceptible and quite substantial. But it is not enough. I would certainly admit that it has not been enough and a lot more remains to be done.

I am sure that the various suggestions put forward by the hon. Members would enable us with the assistance of the State Governments to see that the constitutional provisions and the decisions taken till now about the protection to be afforded to these minority languages would be implemented in every way so that when we come before the House next time, we should be able to give a picture of better implementation.

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East) : I have said that in certain areas the tribal people are concentrated. I have given the Santhals and Oraons, Tripuri in Tripura and some other tribes in Assam and Manipur. I said that for the development of the tribal language in that region some regional body should be set up to deal with the tribal languages and develop them What is the reaction of the Government ? I want a clear answer to that point.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : The development of the language is the responsibility of the Ministry of Education. I shall certainly pass on this suggestion to them. But the difficulty will not be solved by the appointment of a local committee ; the difficulty is about the script.

SHRI DASARATHA DEB : The script is there ; we are using the Bengali script. There will be no difficulty,

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : An experimental school has been started where all these things about Tripura are being examined and full fledged instructions are given. In areas where Tripuri teachers are not available, the teachers teach in Bengali and explain to the pupils in Tripuri. I do not say it meets our requirements but some sort of instructions are given. As I said an experimental school has been set up and that will give us some ideas how further to develop Tripuri. He referred to the regional committee. I do not know if the regional councils that we are going to set up in the North-Eastern area could also take this up as one of its problems and study it in proper perspective. I am sure this will be

kept in view when this question is taken up.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are two substitute motions moved by Mr. Mohanty, Nos. 1 and 2. I shall put them to vote.

The question is :

'That for the original motion, the following be substituted, namely :

"This House, having considered the Eleventh Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period 1st July, 1968 to 30th June, 1969, laid on the Table of the House on the 31st July, 1970, is of the opinion that the office of the Commissioner for linguistic Minorities be abolished as it has failed to properly investigate the problems of the linguistic minorities with a view to safegaurd their constitutional rights as contemplated in article 350B (2) of the Constitution." ' (1)

'That for the original motion, the following be substituted, namely :

"This House, having considered the Eleventh Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period 1st July, 1968 to 30th June, 1969, laid on the Table of the House on the 31st July, 1970, is of opinion that—

(a) special efforts should be undertaken to safeguard the constitutional rights of the Oriya speaking minorities residing in Andhra Pradesh and Bihar ;

(b) the State Governments should insist upon knowledge of regional language as a prerequisite for entry into State services, in keeping with the Central Government's insistence for knowledge of the official language for entry into the Union Services." ' (2).

The motions were negatived.

15.34 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* : CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF MYSORE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : I beg to move :

"That this House approves the continuance in force of the proclamation dated the 27th March, 1971, in respect of Mysore issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 25th November, 1971."

The House will recall the circumstances in which the Proclamation under article 356 of the Constitution had to be issued in relation to the State of Mysore on the 27th March, 1971. It was approved by this House on the 24th May, 1971 and by the other House on 25th May, 1971. In accordance with clause 4 of article 356 the Proclamation will remain in force till 24th November, 1971. It will be possible to revoke the Proclamation only after the elections were held to the legislative assembly and a popular Government comes into office.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : अध्यक्ष महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the Bell be rung.

Now there is quorum. He may continue.

SHRI K. C. PANT : I was saying that it would be possible to revoke the proclamation only after elections are held to the Legislative Assembly and a popular Government comes into office. The Election Commission has undertaken intensive revision of the electoral rolls which has been recently included in the State of Mysore. The House will agree that it will be appropriate to hold elections in Mysore at the time when elections are held to the other Legislatures in 1972. Therefore, revocation of the Proclamation in relation to that State will be possible only after February next year. I have, therefore, come before the House with the request that a further extension of the